भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3119

गुरूवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक)

एआई का रोजगार विस्थापन पर प्रभाव

3119 श्री ए. ए. रहीम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विभिनन क्षेत्रों में रोजगार विस्थापन पर कृत्रिम मेधा (एआई) के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन करवाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार की ऐसा अध्ययन करवाने की मंशा है;

(ग) सरकार द्वारा एआई प्रौद्योगिकियों को अधिकाधिक अपनाने के कारण निजी क्षेत्र में नौकरियों के नुकसान को रोकने या कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने एआई के उपयोग की निगरानी और विनियमन के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार किया है या प्रस्तावित किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इससे बेरोजगारी का संकट और न बढ़े और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): नैसकॉम की अगस्त 2024 में प्रकाशित "एडवांसिंग इंडियाज एआई स्किल्स" रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एआई प्रतिभा के वर्ष 2027 तक 15 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से 6 लाख-6.5 लाख पेशेवरों से 12.50 लाख से अधिक बढ़ने की उम्मीद है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से डेटा साइंस, डेटा क्यूरेशन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन होगा। अब तक, एआई/बिग डेटा एनालिटिक्स प्रौद्योगिकियों के 3.20 लाख अभ्यर्थियों सहित 8.65 लाख अभ्यर्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन/प्रशिक्षण लिया है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने नैसकॉम के साथ संयुक्त रूप से "फ्यूचरस्किल्स प्राइम" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी जनशक्ति का रि-स्किलिंग/अप-स्किलिंग करना है।

इसके अलावा, एमईआईटीवाई ने "नेशनल एआई पोर्टल" (https://indiaai.gov.in/) लॉन्च किया है, जो एआई से संबंधित पहलों, अकादमिक अनुसंधान, स्टार्टअप, नीतिगत विकास और थॉट लीडरशिप संबंधी लेखों का व्यापक संग्रह है। यह पोर्टल नैतिक एआई, तकनीकी प्रगति और उद्योगजगत के रुझानों जैसे विषयों पर वेबिनार और ऑनलाइन सत्र भी आयोजित करता है।

प्रौद्योगिकी के उपयोग का लोकतंत्रीकरण करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को संरेखित करते हुए भारत सरकार 'सभी के लिए एआई' की अवधारणा पर जोर देती है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई समाज के सभी क्षेत्रों को लाभान्वित करे, नवाचार और विकास को आगे बढ़ावा दे। सरकार की नीतियों का उद्देश्य एआई विकास के बीच देश में उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, सरकार स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, शासन और अन्य जैसे क्षेत्रों में देश के लोगों की भलाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

*****